45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों ने दी प्रदेश को रफ्तार

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने 'उद्यम प्रदेश' के तौर पर दिलाई मान्यता देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना यूपी

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों ने उत्तर प्रदेश को नई रफ्तार दी है। बीते आठ वर्षों में आए निवेश के इन प्रस्तावों में से 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। इसके चलते प्रदेश के 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। साथ ही उत्तर प्रदेश 'बीमारू' से 'ब्रेक-थ्रू' प्रदेश बनकर देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन गया है।

वर्ष 2017 से लेकर अभी तक आठ वर्षों में प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, कारोबारी सुगमता में सुधार करने व रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की वजह से उत्तर प्रदेश देश में 'उद्यम प्रदेश' के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में सफल रहा है। बीते आठ वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) दोगुनी होकर 27.51 लाख करोड़ रुपये होने की तरफ अग्रसर है।

औद्योगिक निवेश व रोजगार संवर्धन नीति-2017 के तहत निवेशकों को कर छूट, सब्सिडी और जमीन आवंटन में दी गई सहूलियत ने रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में 33 सेक्टोरल पालिसी लागू की गई, जिससे उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास का केंद्र बना। विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, 2022 में वह दूसरे स्थान पर पहुंच गया।

15 लाख करोड़ के निवेश को उतारा धरातल पर

60 लाख युवाओं को आठ वर्षों में मिला रोजगार

औद्योगिक पार्कों की स्थापना का तेज हुआ काम

प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ-हरदोई में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क की स्थापना पर काम किया जा रहा है।हरदोई व कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क तथा गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर व हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है।

योगी सरकार ने प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए वर्ष 2018 में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआइसी) का आयोजन किया था, जिस पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। वहीं वर्ष 2018 से अब तक हो चुकी चार जीबीसी में करोड़ों रुपये की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में मदद मिली है। एक जिला एक उत्पाद जैसी कई योजनाओं ने प्रदेश के निर्यात को 86 हजार करोड़ से बढ़ाकर दो लाख करोड़ पहुंचाने में सार्थक भूमिका अदा की।

आठ वर्षों में डिफेंस कारिडोर, मेडिकल और फार्मा के क्षेत्र में आए 63,475 करोड़ रुपये के निवेश से स्वास्थ्य सेवाओं और विनिर्माण में रोजगार बढ़ा। एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों और डिजिटल कनेक्टिविटी ने राज्य को निवेशकों के लिए आकर्षक का केंद्र बनाया।

अपना उद्यम शुरू करने को प्रोत्साहित किया : सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जैसी योजना शुरू कर युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए बिना गारंटी व बिना ब्याज के पांच लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।